उर्वरक उत्पादन की अपर्याप्त क्षमता का उपयोग किया जाना

1333. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में उर्वरक इकाइयां अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) गुजरात राज्य में स्थित बड़े उर्वरक एकक क्षमता उपयोगिता के संतोषजनक स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय मैं इफको अपने अमोनिया-यूरिया संयंत्र, कलोल की क्षमता के विस्तर करने के लिए 119 करोड़ रुपए की लागत पर एक परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

ORE mines in Gujarat

1334. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the number of iron ore mines in Gujarat particularly in Kachha region;

(b) the quantum of various grades of iron ore reserved in those mines;

(c) the system adopted at present in each of those mines for the extraction of iron ore; and

(d) the steps taken by Government for the development of iron ore mines in that State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) There are no iron ore mines in the State of Gujarat

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Constitution of Committee to Study the failure of DDA

1335. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of URBAN AFFAIR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Minister of Urban Development had constituted a committee to go into the failure of the DDA in the construction of houses in Delhi;

(b) if so, whether the committee submitted its report and if so, what are the findings of that committee; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYEMNT (SHRI P.K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) and (c) Question does not arise in view of reply to (a) above.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य

1336. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने से सरकार के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा राज्यवार कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संकृति विभाग में उप मंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्रवाई योजना 1992 में नीतिगत घोषणा के अनुसरण में, सामुदायिक सहभागिता तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, प्रौढ़ साक्षरता, और शिक्षा के व्यावसायीकरण की विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन को सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रोत्साहित